



नान्दिग्राम टाइम्स



Monday 8th December 2025

● वर्ष -9

● अंक 222

● पृष्ठ 04

● मूल्य - 2 रूपए

● www.nandigramtimes.com

नाशिक: सप्तश्रृंगी घाट पर कार खाई में गिरी — छह श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

संवाददाता |

नाशिक, 7 दिसंबर 2025 — Saptashrungi Ghat घाट पर एक भयावह सड़क हादसे में छह श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। Toyota Innova (आरटी एमएच-15 BN 0555) कार, जिसमें सात लोग सवार थे, दर्शन कर लौट रही थी। घाट की घुमावदार सड़क पर अनियंत्रित होकर यह कार लगभग 600 फीट गहरी खाई में गिर गई।

मृतकों की पहचान पिंपलगांव बसवंत (निफाड़ तालुका) के रहने वाले पटेल परिवार के सदस्यों — Kirti Patel, Raseela Patel, Vitthal Patel, Lata Patel, Vachan Patel और Maniben Patel के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। हालांकि भारी ढलान और तीव्र गहराई के कारण बचाव एवं शव निकालने का काम काफी मुश्किल रहा।

इस हादसे ने घाटी क्षेत्र की सड़क सुरक्षा वर्कस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन व यातायात अधिकारियों से मांग उठ रही है कि ऐसे खतरनाक व घुमावदार मार्गों पर सुरक्षा उपाय — जैसे मजबूत रेलिंग्स, चेतावनी संकेत व उचित मार्गदर्शन — सुनिश्चित किए जाएँ, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके।

मंत्रिमंडल बैठक | किसानों के लिए 663 करोड़ रुपये की राहत पास

मंत्रिमंडल बैठक: मिलिंद साठे बने राज्य के नए महाधिवक्ता; किसानों के लिए 663 करोड़ रुपये की राहत पास

नागपुर | 7 दिसंबर

2025 — राज्य सरकार की आज नागपुर में हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए, जिनका असर कानून-प्रक्रिया व कृषि क्षेत्र दोनों पर पड़ेगा। सबसे पहले — वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे को अगले आदेश तक राज्य का नया Advocate General of Maharashtra (एजी) नियुक्त किया गया है। इस पद पर अभी तक Birendra Saraf कार्यरत थे, जिन्होंने कुछ महीने पहले व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। मिलिंद साठे का विधिक



किसानों के लिए 663 करोड़ रुपये की राहत पास

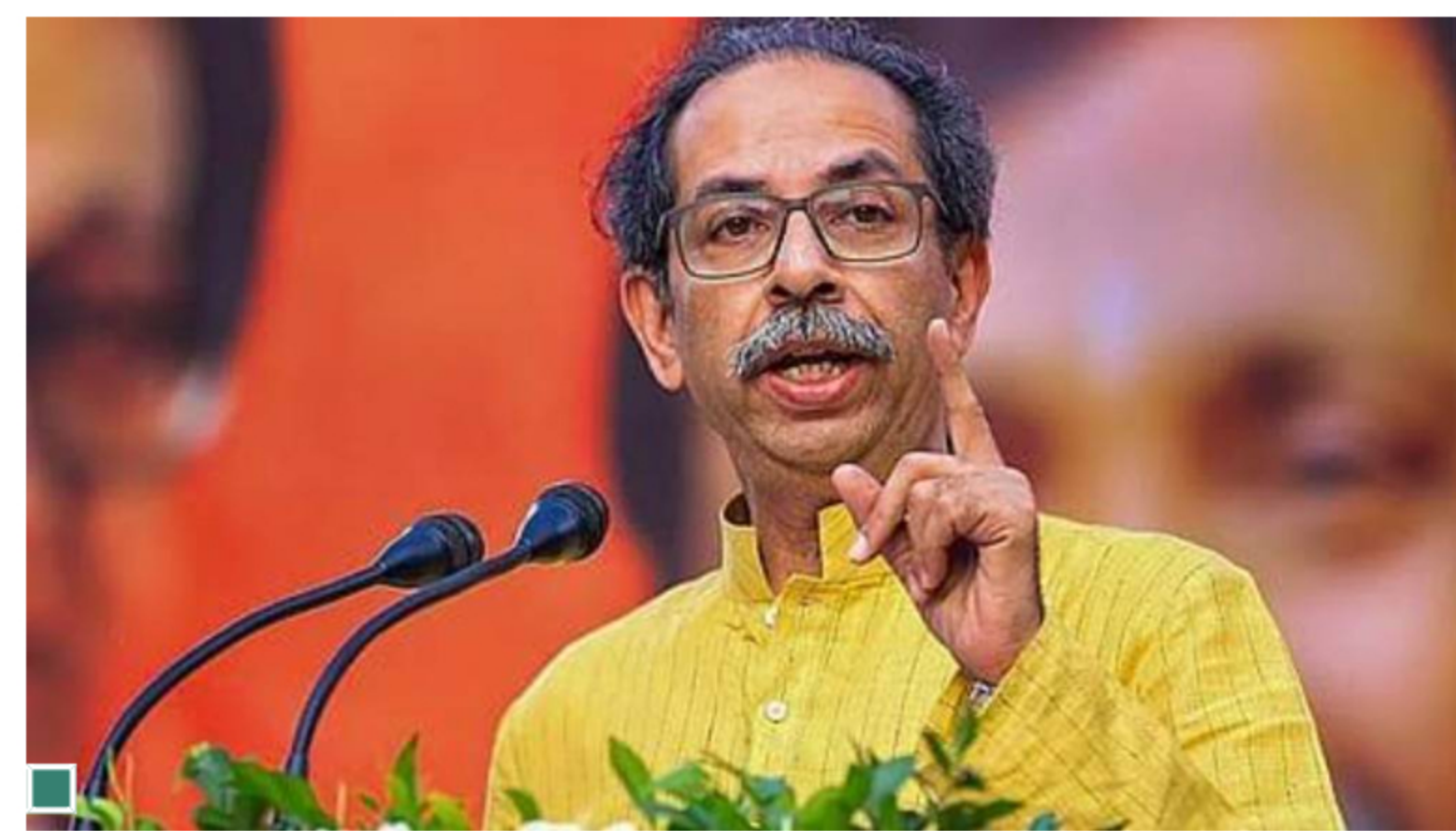
अनुभव गौरतलब है — वे 1982 में बार में शामिल हुए थे, 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता (senior advocate) नामित किए गए और आज तक कई संवेदनशील और सार्वजनिक हित के मामलों में सरकार, सार्वजनिक निकायों और विभिन्न संस्थाओं की पैरवी की है। दूसरा और अहम — बैठक

में राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा राहत प्रस्ताव मंजूर हुआ। अतिवृष्टि व हाल की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित शेतक-र्यांसाठी 663 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है। इस प्रस्ताव के तहत लगभग 10 लाख 67 हजार किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है;

जो धनराशि बकाया है, उसे डायरेक्ट बैंक खाते में भेजा जाएगा — जिससे प्रभावित किसानों को फोरी राहत मिलेगी।

सरकार ने कहा है कि यह फैसला हिवाळी अधिवेशन (विंटर सेशन) के पूर्वसंध्या पर लिया गया है, ताकि विधायक-विधान परिषद सत्र में किसानों का मसला उठने से पहले राहत का भरोसा सुनिश्चित हो सके।

इन दो बड़े निर्णयों को राज्य में व्यापक रूप से प्रशासनिक सुधार और कृषि-सहायता की दिशा में कदम माना जा रहा है। नए महाधिवक्ता साठे का अनुभव न्यायिक चुनौतियों से निपटने में सरकार के लिए सहायक साबित हो सकता है, जबकि किसान राहत पैकेज प्रभावित कृषि क्षेत्र को आर्थिक सुरक्षा देगा।



विरोधी नेता नहीं, तो 'उपमुख्यमंत्री' पद भी रद्द करना चाहिए : उद्धव ठाकरे

मुंबई — उद्धव ठाकरे ने शनिवार को राज्य सरकार से मांग की है कि यदि विधानसभे में कोई आधिकारिक विरोधी पक्षनेता (Leader of Opposition) नहीं बनाया जा सकता, तो Deputy Chief Minister of Maharashtra का पद रद्द कर देना चाहिए। उनका कहना है कि यह पद संवैधानिक नहीं है, इसलिए जब लोकतांत्रिक आपात-स्थिति में संवैधानिक पद खाली पड़ रहा है, तो असंवैधानिक पद बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं।

ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार विरोधी पक्ष की उपेक्षा कर रही है — “यदि विपक्ष के लिए नियमों को बहाना दिया जा रहा है, तो असंवैधानिक उप-मुख्यमंत्री पद क्यों कायम रखा गया है?” उन्होंने कहा कि यदि जरूरी हो, तो उन मंत्रियों को मंत्री ही बनाएं जिनके पास विभाग या खाता है — लेकिन किसी को ‘उपमुख्यमंत्री’ का टाइटिल न दिया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं।

मतदाता सूची घोटाले और चुनावों में कथित हेरफेर के पैकेज-मामले को उठाते हुए ठाकरे ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक आधारों का पालन होना चाहिए।

ठाकरे के इस प्रकार के बयानों ने राज्य की राजनैतिक हवा में नया उबाल ला दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है, और क्या दोनों सदनों में विपक्षी नेता नियुक्त होंगे — या फिर उपमुख्यमंत्री पद रद्द होगा।

इंडिगो संकट पर सियासी घमासान... राहुल गांधी के 'सरकारी मोनोपोली' वाले आरोप का केंद्रीय मंत्री ने दिया करारा जवाब



संवाददाता | NEWS AGENCY

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और देरी से यात्रियों को हो रही भारी परेशानी पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि चार डीजीसीए अधिकारियों की टीम इस मामले की विस्तृत जांच करेगी और इसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी की 'सरकारी मोनोपोली मांडें' वाली टिप्पणी पर जोरदार पलटवार किया है।

राहुल गांधी को दिया करारा जवाब उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि यह जनता से जुड़ा मामला है और इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार उड्डयन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। ज्यादा प्रतिस्पर्धा का मतलब है, नई एयरलाइंस को आने देना, हमारे बेड़े में ज्यादा विमान जोड़ना और लीजिंग लागत कम करना। हमने संसद में इसी उद्देश्य से कानून भी पारित किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा विमान जोड़े जा सकें।



अब 9 व 12 दिसंबर को नागपुर में नया आंदोलन

नागपुर / सोलापूर, 7 दिसंबर 2025 — राज्य में 5 दिसंबर को हुए शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मी आंदोलन के बाद अब 35,000 से अधिक शिक्षकों की एक दिन की सैलरी कटौती की जाएगी। उक्त आंदोलन के दौरान करीब 24,000 स्कूल — जिनमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर शामिल थे — पूरी तरह बंद रहे। शिक्षकों का यह बंद आंदोलन, Maharashtra State Teachers and Non-Teaching Staff Coordination Committee और अन्य शिक्षक

महाराष्ट्र में 35 हजार शिक्षकों का एक दिन का वेतन कटा — 24 हजार से ज्यादा स्कूल रहे बंद; अब 9 व 12 दिसंबर को नागपुर में नया आंदोलन

संघटनाओं द्वारा बुलाया गया था। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल थे — अनिवार्य Teacher Eligibility Test (TET) व्यवस्था को हटाना, संच-मान्यता (school recognition) में सुधार, संविदा तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की स्थिति को नियमित करना, और पूर्व पेंशन योजना (old pension scheme) पुनर्स्थापित करना।

शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में हजारों शिक्षक बिना अनुमति लिए हड़ताल में शामिल हुए। शिक्षा विभाग के अनुसार, प्राथमिक स्तर की लगभग 21,477 और माध्यमिक स्तर की 2,539 स्कूलें बंद पाई गईं। आंदोलन में दोनों विभागों के कुल 35,000 से अधिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मी शामिल थे।

हालाँकि, विभाग ने पहले ही निर्देश जारी किया था कि 5 दिसंबर को सभी स्कूल खुलेंगे — सरकार, अनुदानित, अनुदान-

रहित, सभी प्रकार के स्कूलों को इस हड़ताल एवं बंद आंदोलन के बावजूद नियमित संचालन जारी रखने को कहा गया था। जिन्हें शिक्षक-कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया, उन्हें “काम नहीं — वेतन नहीं” की नीति के तहत पगार काटने का आदेश दिया गया है।

अब शिक्षक संघटनाओं ने 9 व 12 दिसंबर को दो नए चरणों में आंदोलन करने का ऐलान किया है — जिनकी अगुवाई करने वाले नेताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो व्यापक हड़ताल हो सकती है।

शिक्षकों का यह आंदोलन महाराष्ट्र में शिक्षा क्षेत्र के हालात, भर्ती प्रक्रिया, पेंशन योजना और कर्मचारी सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों को लेकर है। इसलिए, इसके आगे के रुझान और सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की निगरानी है।



नांदेड ZP में 41 सेवकों को पदोन्नति — कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति

संवाददाता | NANDED

नांदेड — जिला परिषद नांदेड में कार्यरत 41 सेवकों को शुक्रवार को कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति दी गई। परिचर/सेवक वर्ग के अनेक कर्मचारी बी.ए. योग्यता के आधार पर मिलने वाली इस पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाल ही में शासन ने विशेष निर्णय जारी कर ऐसे पात्र सेवकों को कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति देने की मंजूरी दी थी।

इसी के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली और उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार ने 41 सेवकों को पदोन्नति आदेश जारी किए। साथ ही दो वरिष्ठ सहायकों को भी अधीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।



(नई दिल्ली, 7 दिसम्बर)
केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए निर्धारित छह माह की समय-सीमा 6 दिसंबर की रात 11:59 बजे समाप्त हो गई।

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की डेडलाइन खत्म; सरकार ने तीन माह की राहत दी, ट्रिब्यूनल से ही एक्सटेंशन संभव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरें रिज्जि ने स्पष्ट किया कि अब इस डेडलाइन में किसी भी तरह का विस्तार संभव नहीं है। यह समय-सीमा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत विधिक रूप से निर्धारित थी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4.6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का विवरण UMEED पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। हालांकि, देशभर में मौजूद करोड़ों वक्फ संसाधनों के मुकाबले यह संख्या अभी भी कम है। कई मुतवल्ली (संपत्ति प्रबंधक) तकनीकी दिक्कतों, दस्तावेजों की कमी या अन्य कारणों से अंतिम समय तक पंजीकरण पूरा नहीं कर पाए।

नए अपडेट के अनुसार, सरकार ने इन मुतवल्लियों के लिए तीन माह की अस्थायी राहत घोषित की है। इस दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। जिन संपत्तियों का पंजीकरण अब तक नहीं हुआ, उनके लिए अब केवल वक्फ ट्रिब्यूनल से ही छह माह तक का एक्सटेंशन लिया जा सकता है। यह कदम प्रशासनिक सहूलियत देने और पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कुछ राज्यों ने इस प्रक्रिया में सफलता भी हासिल की है। कर्नाटक ने अपनी सभी वक्फ संपत्तियों का डेटा UMEED

पोर्टल पर पूरी तरह अपलोड कर दिया है, जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन गया है। मंत्री रिज्जि ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह कानून आधारित है और इसमें न तो राजनीतिक दबाव है और न ही मनमाना निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय-सीमा की वैधता माना है। वक्फ संपत्तियों का यह पंजीकरण कदम न केवल प्रशासनिक सुधार को मजबूती देगा, बल्कि अवैध कब्जों और पारदर्शिता की कमी को दूर करने में भी मदद करेगा। इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए इन संपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होने की संभावना बढ़ेगी।



नांदेड में तुअर की फसल में छिपाई गई गांजा खेती का भंडाफोड़, ₹1.60 लाख का माल जब्त



नांदेड के किनवट तालुका के शिवणी परिसर में पुलिस ने एक किसान की तुअर की फसल के बीच छिपाई गई अवैध गांजा खेती का भंडाफोड़ किया। गुप्त जानकारी के आधार पर सपोनी उमेश भोसले और उनकी टीम ने छापा मारकर गजानन नारायण आडे (55) के खेत से सुका व हरा गांजा मिलाकर करीब ₹1.60 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनाश कुमार व उपविभागीय अधिकारी बोंडवे के मार्गदर्शन में की गई। समाचार लिखे जाने तक मामले में गुन्हा दर्ज नहीं हुआ था। पुलिस आगे की जांच में जुटी है।

वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन — इतिहास, वर्तमान और नई स्थिति: क्या वक्फ भविष्य के लिए सुरक्षित हैं?



संपादकीय...
नांदेड़ (महाराष्ट्र), 8 दिसंबर 2025)

UMEED पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, 2025 में लागू हुए Waqf (Amendment) Act, 2025 का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल सरकार द्वारा वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस नए कानून के अंतर्गत, पहले से WAMSI पोर्टल पर दर्ज लगभग 8.72 लाख वक्फ संपत्तियाँ, जिनका क्षेत्रफल 38 लाख एकड़ से अधिक बताया गया है, अब UMEED में पुनः पंजीकृत करनी थीं।

इन 8.72 लाख संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, धार्मिक स्कूल, जमीन-जायदाद, खेती की जमीन और किरायानुमा संपत्तियाँ शामिल हैं। इनमें से लगभग 4.02 लाख संपत्तियाँ “वक्फ बाय यूजर” (Waqf by user) थीं, जो सीधे मुतवल्ली या प्रबंधकों द्वारा संचालित की जाती हैं।

6 जून 2025 को UMEED पोर्टल का शुभारंभ किया गया और सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण — भौगोलिक जानकारी, माप, दस्तावेज आदि — छह माह के भीतर (5-6 दिसंबर 2025 तक) अपलोड करना अनिवार्य किया गया।

लेकिन वास्तविकता इससे काफी भिन्न रही। शुरुआती महीनों में केवल 69 “makers of waqf” ने संपत्ति विवरण सबमिट किया, जबकि 663 ने प्रक्रिया शुरू की थी, पर किसी संपत्ति को तत्काल स्वीकृति नहीं मिली। समय सीमा के भीतर विभिन्न राज्यों में पंजीकरण धीमा रहा। उदाहरण के लिए, Uttar Pradesh Sunni Waqf Board के पास 1.26 लाख संपत्तियाँ थीं, लेकिन 7 नवंबर तक केवल 15,000 ही पंजीकृत हो सकीं।

कर्नाटक राज्य ने इस प्रक्रिया में बेहतर तत्परता दिखाई। Karnataka State Waqf Board ने 5 दिसंबर तक अपनी सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण UMEED पर अपलोड कर दिया, जो अन्य राज्यों के लिए आदर्श उदाहरण बन गया।

6 दिसंबर 2025 को निर्धारित डेडलाइन समाप्त होने के साथ, केंद्र सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि अब इस पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कोई सामान्य “जनरल विस्तार” नहीं दिया जाएगा।

हालाँकि, जिन वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हो सका, उनके लिए मुतवल्ली या वक्फ प्रबंधक अब व्यक्तिगत मामलों में वक्फ ट्रिब्यूनल (Waqf Tribunal) से छः माह तक का एक्सटेंशन ले सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने राहत देते हुए यह भी घोषणा की है कि डेडलाइन के बाद तीन माह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि तकनीकी या दस्तावेजी कठिनाइयों का सामना करने वाले प्रबंधकों को समय मिल सके।

निष्कर्षतः, भारत में वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक महत्व रखता है। 8.72 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियाँ, 38 लाख एकड़ से अधिक भूमि — अब डिजिटल पंजीकरण के माध्यम से समुदाय, सरकार और न्याय व्यवस्था के सामने स्पष्ट रूप में आएंगी।

इसकी सफलता के लिए बाकी राज्यों से भी कर्नाटक जैसी तत्परता और प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है। ट्रिब्यूनल प्रक्रियाओं को शीघ्र और न्यायसंगत बनाना होगा। अन्यथा, लाखों वक्फ संपत्तियाँ — धर्म, शिक्षा और समाज सेवा के उद्देश्य से — खोने या दुरुपयोग का खतरा बना रह सकता है।

अतः, 2025 का यह वक्फ पंजीकरण अभियान — यदि पूरी तरह लागू हुआ — वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, दुरुपयोग की रोक और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का मजबूत आधार बनेगा।

बाबासाहेब आंबेडकर | महापरिनिर्वाण दिवस पर विचार,

बाबासाहेब आंबेडकर: महापरिनिर्वाण दिवस पर विचार, विवेक और वैचारिक प्रतिबद्धता का संकल्प

● संपादकीय...

6 दिसंबर का दिन भारतीय इतिहास में केवल एक तिथि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को झकझोर देने वाला अवसर है — वह दिन जब भारत ने अपने महानतम मनीषियों में से एक, भारतीय संविधान के शिल्पकार, विश्वरत्न और भारतरत्न “डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर” को खो दिया। यह दिन आंबेडकर के महापरिनिर्वाण का स्मरण कर हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा लेने का अवसर देता है। आज जब देश असमानता, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक असंतुलन जैसे प्रश्नों से जूझ रहा है, तब आंबेडकर का चिंतन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठता है।

बाबासाहेब का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय समाज की वह यात्रा है, जिसने सदियों से स्थापित असमानता, छुआछूत और जातिगत अवरोधों को चुनौती दी।

अछूत बस्ती की मिट्टी से उठकर वैश्विक बौद्धिकता के शिखर तक पहुँचने वाला उनका संघर्ष हमें



बताता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल नारों से नहीं, बल्कि साहस, ज्ञान और निरंतर संघर्ष से संभव होता है। उन्होंने संविधान की रचना मात्र कानून के तौर पर नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन के उपकरण के रूप में की। उनका स्पष्ट मत था कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक संरचना नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार है—और जब तक समाज समतामूलक नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र भी अधूरा रहेगा।

आज महापरिनिर्वाण

दिवस पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हम आंबेडकर के सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या समाज में वह समानता है जिसकी परिकल्पना उन्होंने की थी? क्या वंचित वर्गों को वह अवसर मिले जिनके लिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन संघर्ष में लगा दिया? शिक्षा से लेकर रोजगार तक, सामाजिक सम्मान से लेकर आर्थिक सुरक्षा तक—कई क्षेत्रों में प्रगति अवश्य हुई है, लेकिन जातिगत भेदभाव, असमानता, नफरत और सामाजिक हिंसा आज भी भारत

की राह में बाधा बने हुए हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिए, परंतु कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों की समझ अभी भी अधूरी है।

आंबेडकर का एक महत्वपूर्ण संदेश था — “शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो”। यह केवल नारा नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का सूत्र है। आज जब सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें, विभाजनकारी विचार और भ्रामक सूचनाएँ तेजी से फैलती हैं,

तब आंबेडकर की शिक्षा और विवेक पर आधारित चेतना और भी आवश्यक हो जाती है। समाज तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक सच्चाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संविधान के मूल्यों को अपनाए।

महापरिनिर्वाण दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि आंबेडकर केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि जीवित विचारधारा हैं। वह विचारधारा जो समान अवसर, न्याय, मानव गरिमा और भाईचारे पर आधारित है। उनकी विरासत को मनाना केवल कार्यक्रमों, घोषणाओं या राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए—बल्कि उसे व्यवहार में उतारने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

आज आवश्यकता है कि देश आंबेडकरवादी सोच को केवल स्मारकों और प्रतिमाओं तक न सीमित रखे, बल्कि उसे शासन, समाज और शिक्षा के केंद्र में रखे। यही बाबासाहेब की सच्ची आदरांजली होगी—कि हम एक ऐसा भारत बनाएँ जहाँ जाति नहीं, क्षमता निर्णायक हो; भेदभाव नहीं, समानता आधार हो; और जहाँ हर नागरिक संविधान की भावना को अपने जीवन में लागू करे।

Indigo Crisis: इंडिगो का अहंकार बना काल? ₹18000 सैलरी, 1 से 3 का काम, कर्मचारी की चिट्ठी ने खोली पोल



नई दिल्ली: इंडिगो के एक कर्मचारी का खुला पत्र सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कर्मचारी ने पत्र लिखकर कंपनी के अंदर सालों से चल रही समस्याओं, कर्मचारियों के बढ़ते संकट और मैनेजमेंट की अनदेखी का खुलासा किया है।

इसमें कर्मचारी ने बताया है कि कैसे भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो धीरे-धीरे अंदर से खीखली हो गई। यह सब रातों-रात नहीं हुआ। इसके बजाय यह सालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करने, काम करने में दबदबे से खुश थे। लेकिन, कर्मचारी का कहना है कि यह सब स्टाफ की भलाई और ऑपरेशनल व्यवस्था की कीमत पर हुआ।

पत्र लिखने वाले कर्मचारी ने बताया कि 2006 में जब इंडिगो शुरू हुई थी, तब टीम को अपने काम पर गर्व था। लेकिन, धीरे-धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया और विकास लालच में। कंपनी के अंदर एक नई सोच पनपने लगी— हम इतने बड़े हैं कि फेल नहीं हो सकते।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि इंडिगो ने जानबूझकर कुछ रूट्स पर बहुत ज्यादा फ्लाइट्स चलाई ताकि दूसरी एयरलाइंस, जैसे नई आई आकासा एयर को नुकसान हो। यात्री भले ही इंडिगो की समय की पाबंदी और बाजार में दबदबे से खुश थे। लेकिन, कर्मचारी का कहना है कि यह सब स्टाफ की भलाई और ऑपरेशनल व्यवस्था की कीमत पर हुआ।

ठीक से ईमेल न लिख पाने वालों को ऊंचे पद पत्र का एक बड़ा हिस्सा कंपनी में बढ़ते हुए ऊंचे पदों के बारे में है। कर्मचारी का दावा है कि ऐसे लोग भी वाइस प्रेसिडेंट बन गए जो ठीक से ईमेल भी नहीं लिख पाते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन पदों से ESOPs (कर्मचारियों को शेयर देने की योजना) और पावर

मिलती थी।

18K रुपये की सैलरी में तीन लोगों का काम हर महीने सिर्फ 16,000-18,000 रुपये पाने वाले ग्राउंड स्टाफ को अत्यधिक दबाव में काम करना पड़ता था। वे 'तीन लोगों का काम' करते थे। उन्हें विमानों के आसपास तेजी से दौड़ना पड़ता था और एक साथ कई काम संभालने पड़ते थे। पत्र में बताया गया है कि कर्मचारी भावनात्मक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। केबिन कृ यात्रियों का स्वागत करने के बीच गैली (रसोई) में रोते थे। इंजीनियरों को बिना किसी खास देखरेख या आराम के एक साथ कई विमानों पर काम करना पड़ता था।

World News | **पुतिन के भारत दौरे के तुरंत बाद रूस ने दिया धोखा?**

पुतिन के भारत दौरे के तुरंत बाद रूस ने दिया धोखा? चीन के साथ की जॉइंट एंटी-मिसाइल ड्रिल, बढ़ेगी टेंशन



मॉस्को: रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बीच चीन के साथ तीसरी जॉइंट एंटी-मिसाइल ड्रिल की है। इस दौरान दोनों देशों के युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने जापान सागर में दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने का अभ्यास किया। इसके अलावा दुश्मन के प्रमुख मिसाइल इंस्टॉलेशन को नष्ट करने का भी अभ्यास किया गया। इसे दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास इसलिए भी अहम है, क्योंकि इसे पुतिन के भारत दौरे के बीच में आयोजित किया गया। चीन और भारत की पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में रूस के इस अभ्यास को एक रणनीतिक बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है।

चीन रक्षा मंत्रालय ने क्या बताया

चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने शनिवार देर रात कहा कि चीन और रूस ने दिसंबर की

शुरुआत में रूसी इलाके में अपनी तीसरी जॉइंट एंटी-मिसाइल ड्रिल की। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर एक पोस्ट के मुताबिक, ये एक्सरसाइज किसी तीसरे पक्ष को टारगेट करके या किसी मौजूदा इंटरनेशनल हालात के जवाब में नहीं की गई थी। दोनों देशों ने पिछले महीने मिसाइल डिफेंस और स्ट्रेटिजिक स्टेबिलिटी पर बातचीत की और अगस्त में जापान सागर में आर्टिलरी और एंटी-सबमरीन ड्रिल की।

रूस-चीन में नो-लिमिट स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप

रूस और चीन ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले से कुछ समय पहले एक "नो-लिमिट" स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप पर साइन किए थे, जिसमें अपनी सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन की रिहर्सल के लिए रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज करने का वादा किया गया था। दोनों देशों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के

"गोल्डन डोम" मिसाइल शील्ड बनाने के प्लान और 30 साल से ज्यादा के ब्रेक के बाद न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग फिर से शुरू करने के उनके बताए गए इरादे पर चिंता जताई है।

भारत की बढ़ सकती है टेंशन

चीन और रूस के बीच बढ़ते रक्षा संबंध भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कारण भविष्य में भारत की टेंशन भी बढ़ सकती है। हालांकि, रूस का कहना है कि उसके चीन के साथ संबंधों का भारत पर कोई असर नहीं होगा। चीन और भारत के बीच पुराना सीमा विवाद है। दोनों देशों ने 1962 में भयंकर युद्ध भी हो चुका है। इसके अलावा भी चीन और भारत में कई बार सीमा संघर्ष होते रहे हैं। इस कारण अगर रूस के कारण चीन की सैन्य ताकत बढ़ती है तो वह भारत के लिए परेशानी की बात होगी।

इजरायल ने ऐसा क्या किया कि घुटनों पर आया अमेरिका, लेबनान से लगाई भीख की गुहार, बोला- मेरा सामान लौटा दो

बेरुत: अमेरिका ने लेबनान से GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम को लौटाने को कहा है। यह बम इजरायली वायुसेना ने कुछ हफ्ते पहले बेरुत की ओर ऑपरेशन के दौरान लॉन्च किया था। इस हमले में हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर अली तबातबाई मारे गए थे। हालांकि, यह GBU-39 बम फटने में नाकाम रहा था। अमेरिका को डर है कि यह बम रूस या चीन के हाथों में पड़ सकता है। इस कारण अमेरिका ने लेबनान की सरकार से इस बम को वापस करने की गुहार लगाई है। हालांकि, लेबनान सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

F-35 का पसंदीदा हथियार है GBU-39 बम छोटे डायमीटर वाले बम (SDB) का पहली बार 2006 में इस्तेमाल किया गया था। ग्लाइड बम क्या है?



GBU-39 एक ग्लाइड बम है जिसे बोइंग ने बनाया है। लॉन्च होने के बाद, यह अपने पंख फैला लेता है और 110 km तक ग्लाइड कर सकता है, भले ही इसका अपना इंजन न हो, जिससे बम को डिप्लॉय करते समय एयरक्राफ्ट रेंज से बाहर रह सकता है। इंजन न होने की वजह से, यह काफी सस्ता भी है, जिसकी कीमत सिर्फ लगभग \$50,000 है। ग्लाइड बम अब कम नहीं हैं, लेकिन इसकी खासियत इसका खास वारहेड है, जिससे यह अपने वजन के मुकाबले काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें कंक्रीट की इमारतों में घुसने की क्षमता भी शामिल है।

GBU-39 की खासियतें जानें लगभग 110 kg वजनी और कॉम्पैक्ट GBU-39 जैसे चार को एक टन के मार्क 84 बम की जगह ले जाया जा सकता है, जिससे एक फाइटर जेट एक ही बार में दर्जनों टारगेट पर हमला कर सकता है। GBU-39 में GPS और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम भी हैं, जिन्हें इम्पैक्ट पर 1 मीटर तक की सटीकता देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे और बम लॉन्च करने की जरूरत कम होती है, दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए खतरा कम होता है, और पर्यावरण को होने वाले नुकसान और पैसे की लागत कम होती है।

WORLD NEWS | **भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं।**

पाकिस्तान की चापलूसी, रिश्त और... पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बड़ा दावा- बताया किस वजह से बिगड़े US-भारत के रिश्ते



भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं।

वॉशिंगटन: अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने कहा है कि पाकिस्तान ने चापलूसी और रिश्त का सहारा लेते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब किया है। रुबिन ने कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत से रिश्ते को साध नहीं पाए हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अमेरिका के दूर होकर भारत अब रूस के करीब जा रहा है। उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में उनका जोरदार स्वागत हुआ और पुतिन ने भी भारत को बेरोकटोक फ्यूल देने का वादा किया है।

माइकल रुबिन ने कहा, 'अमेरिकी नागरिक ट्रंप के उन कामों से हैरान हैं, जिनसे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रिश्ते बिगड़े हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली से क्यों चीजें खराब की। शायद पाकिस्तानियों ने ट्रंप की चापलूसी से ऐसा किया। या फिर पाकिस्तान, तुर्की और कतर में उनके सपोर्टर्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को रिश्त ने यह किया। हम कह सकते हैं कि यह ऐसी रिश्त है, जो आने वाले कई दशकों तक अमेरिका को रणनीतिक घाटे में डालेगी।'

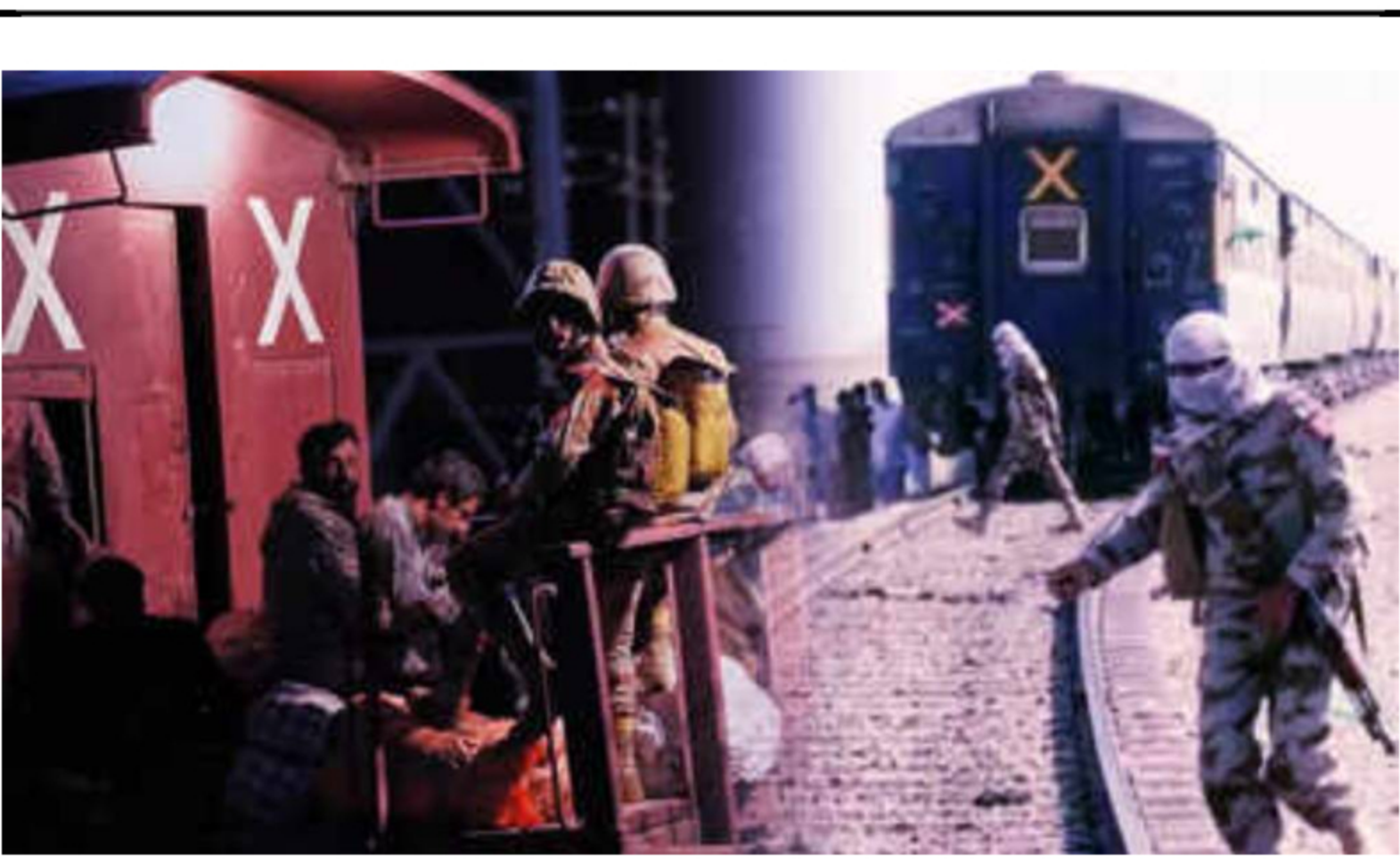
भारत को लेकर ना दे अमेरिका

रुबिन ने ANI से कहा कि अमेरिका की ओर से भारत को रूसी तेल ना खरीदने के लिए लेकर दिया जा रहा है। यह पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि वॉशिंगटन खुद मॉस्को के साथ व्यापार कर रहा है। ऐसे में अगर अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए नई दिल्ली मॉस्को से व्यापार करता है तो इसमें गलत क्या है।

रुबिन ने आगे कहा, 'अमेरिकियों को यह समझ में नहीं आता है कि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। उसे बड़े

पैमाने पर एनर्जी की जरूरत है। ऐसे में अमेरिका को भारत को सस्ते दाम पर ईंधन देना चाहिए। ना कि सिर्फ उसे रूस से तेल खरीद रोकने की नसीहत देनी चाहिए।

मुनीर को सम्मान देना गलत रुबिन ने असीम मुनीर के जून में वॉइड हाउस दौरे को लेकर भी ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर को अमेरिका आने पर सम्मान देने के बजाय गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पाकिस्तान से दोस्ती के पीछे कोई रणनीतिक तर्क नहीं है। इसे आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाला देश घोषित कर देना चाहिए।



पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर हमले की कोशिश, ट्रेन को विस्फोटक से उड़ाने की थी प्लानिंग

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन पर हमले की कोशिश की है। पाकिस्तानी सेना और सुरक्षाबलों का दावा है कि शनिवार को ट्रेन में भीषण धमाका किया जाने की योजना थी लेकिन समय रहते इसे नाकाम कर दिया गया। यह ट्रेन बीते कुछ महीनों से लगातार बलूच विद्रोहियों को निशाने पर है। इस साल मार्च में बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अगवा करते हुए सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। इससे पाकिस्तानी सेना और सरकार की दुनियाभर में किरकिरी हुई थी।

डॉन की रिपोर्ट खबर के अनुसार, पेशावर जाने वाली ट्रेन की पटरी पर शनिवार को बलूचिस्तान के नसीराबाद इलाके में अज्ञात चरमपंथियों ने

विस्फोटक लगा दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोटक के बारे में सूचना मिलने के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर ली और बम को समय रहते निष्क्रिय कर दिया। ट्रेन में विस्फोटक लगाने वाली गुट की जानकारी सामने नहीं आई है।

निशाने पर जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं है, जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया है या इसकी कोशिश की गई है। इस ट्रेन को खासतौर से अशांत बलूचिस्तान में बार-बार निशाना बनाया गया है। इसके चलते कई बार इस ट्रेन को हालिया महीनों में कैसिल तक करना पड़ा है। ट्रेन को अगवा करने की धमकियों और खुफिया सूचनाओं के चलते रद्द किया गया है।

सऊदी अरब | **सरकार ने हज यात्रियों के लिए जारी किए नुस्क कार्ड के नए नियम**

सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रियों के लिए जारी किए नुस्क कार्ड के नए नियम, कई अहम बदलाव, जानें भारतीयों पर असर

● NEWS AGENCY

रियाद: सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। हज मंत्रालय ने कहा है कि नए नुस्क कार्ड नियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों हाजियों के लिए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि हज और उमराह को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए ये कदम उठाया है। हज और उमराह मंत्रालय का नुस्क कार्ड अब घरेलू लोगों के लिए डिजिटल रूप में और विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए प्रिंटेड रूप में उपलब्ध है। भारतीय बड़ी संख्या में हज के लिए जाते हैं, ऐसे में भारतीय मुस्लिमों को भी इससे आसानी होगी। हज और उमराह मिनिस्ट्री के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडरसेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल अजीज अल-मुताहमी ने बताया



कि नुस्क अल-उमराह नाम की इस पहल का मकसद जरूरी तीर्थ सेवाओं को एक ही इस्तेमाल में आसान कार्ड में एक जगह इकट्ठा करना है। यह नुस्क अल-उमराह कार्ड तीर्थयात्रियों के लिए कई सीधी सेवाओं की सुविधा देता है। यह बिना किसी रुकावट के तीर्थ यात्रा के लिए एक यूनिफाइड कार्ड है। यह नुस्क अल-उमराह कार्ड से मिलने वाली सेवाएं!

यह कार्ड तीर्थ यात्रा के लॉजिस्टिक पहलुओं को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। इससे तीर्थयात्रियों को जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है।

ट्रांसपोर्ट सेवा के तहत तीर्थयात्री शटल और बस सेवाओं को इस कार्ड से मैनेज और एक्सेस कर सकते हैं। क्राउड मैनेजमेंट में यह कार्ड अधिकारियों को खास तीर्थ क्षेत्रों में सुरक्षित आने-जाने में मदद करता है।

यह कार्ड यह ट्रांसपोर्टेशन गाइडों के लिए ईंधन भरने को आसान बनाता है, जिससे देरी कम होती है। साथ ही इस कार्ड से तीर्थयात्री आसानी से रहने की जगह और तय ट्रांसफर पा सकते हैं। इसके अलावा सेवाओं की बात की जाए तो यह कार्ड तीर्थयात्रा का अनुभव आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए कई और जरूरी बातों को भी कवर करता है।

सऊदी लोगों को लिए सहूलियत सऊदी अरब के निवासी इस कार्ड का इस्तेमाल अपने मोबाइल फोन पर डिजिटल रूप से कर सकते हैं। वहीं जो तीर्थयात्री विदेश से आ रहे हैं, उन्हें यह कार्ड पहुंचने पर प्रिंटेड रूप में मिलेगा। इस दोहर तरीके से यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी तीर्थयात्रियों के लिए यह कार्ड सुलभ हो, चाहे वे कहीं से भी आए या तकनीक का कितना भी इस्तेमाल करते हों।



नंदिग्राम टाइम्स



Mon 8th December 2025 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 222 | ● पृष्ठ 04 | ● RNI-MAHHIN/2016/69743 | ● www.nandigramtimes.com



हिमायतनगर में तेंदुए का हमला
— किसान बाल-बाल बचा

हिमायतनगर (नांदेड़) – बड़ागांव तांडा क्षेत्र में शनिवार सुबह मवेशी चराने गए किसान उल्लास अनिल जाधव पर झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। तेंदुए के झपट्टा मारते ही किसान घबराए नहीं, बल्कि जोर-जोर से चिल्लाते हुए प्रतिरोध करते रहे।

किसान की चीख सुनकर पास चर रहे मवेशियों का झुंड उनकी ओर दौड़ पड़ा और तेंदुए के सामने आक्रामक हो गया। मवेशियों की हरकत और आसपास मौजूद किसानों की हलचल देखकर तेंदुआ डरकर जंगल की ओर भाग गया। घटना में उल्लास के कपड़े फट गए और उन्हें मामूली चोटें आईं, लेकिन वे बड़े हादसे से बच गए।

यह क्षेत्र वनक्षेत्र की सीमा से सटा होने के कारण लगातार मानव-वन्यजीव संपर्क होता रहता है। प्रशासन ने किसानों और ग्रामीणों से सतर्क रहने, अकेले खेतों में न जाने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।

NANDED NEWS | नांदेड़ में 'रेत माफिया' के लिए तहसीलदार पर हमला

नांदेड़ में 'रेत माफिया' के लिए तहसीलदार पर हमला — भ्रष्ट तलाठी की करतूत से राजस्व विभाग में हड़कंप

नांदेड़ | नांदेड़ जिले के अर्धापुर तहसील में रेत माफिया और भ्रष्ट कर्मचारियों की सांठगांठ उजागर करने वाली हैरान करने वाली घटना सामने आई है। अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए कार्रवाई पर निकले प्रभारी तहसीलदार राजेश शिंदे पर उनके ही अधीनस्थ तलाठी प्रदीप पाटिल ने हमला कर दिया। इस घटना ने पूरे राजस्व विभाग में खलबली मचा दी है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब विभाग के ही कर्मचारी माफिया के 'मित्र' बन जाएं, तो कार्रवाई कौन करेगा? प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभारी तहसीलदार राजेश शिंदे अवैध रेत उपसा और



परिवहन के खिलाफ अभियान चला रहे थे। कार्रवाई के दौरान चार अवैध रेत लदे वाहनों को जब्त किया गया। इसी बीच, स्थानीय रेत तस्करों से कथित रूप से संबंध रखने वाला तलाठी प्रदीप पाटिल मौके पर पहुंचा और कार्रवाई का विरोध करते हुए तहसीलदार से विवाद करने लगा। विवाद इतना



बढ़ा कि उसने तहसीलदार शिंदे पर हाथ उठा दिया। घटना के बाद तहसीलदार की शिकायत पर अर्धापुर पुलिस थाने में तलाठी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। राजस्व विभाग की रीढ़ माने जाने वाले पद पर बैठे कर्मचारी की यह हरकत प्रशासन के लिए गंभीर चिंता

का विषय बन गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 26 नवंबर को अवैध रेत कारोबार पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जिनमें 30 दिनों से लेकर स्थायी रूप से वाहन परमिट रद्द करने तक की कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। परंतु अर्धापुर की घटना ने यह साबित कर दिया कि जब भ्रष्टाचार विभाग के भीतर ही पनपेगा, तो किसी भी कानून की प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आना स्वाभाविक है।

अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी तंत्र के ही कुछ कर्मचारी माफिया के संरक्षण में उतर आए हैं, तो रेत माफिया की दहशत और अवैध कारोबार पर कैसे अंकुश लगेगा?



छत्रपति संभाजीनगर

बोगस IAS प्रकरण : चौथे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

छत्रपति संभाजीनगर — फर्जी IAS अधिकारी बनकर बड़े स्तर पर ठगी करने वाली कल्पना भगवत प्रकरण में सिडको पुलिस ने चौथे आरोपी दत्तात्रय पांडुरंग शेटे (38), निवासी मंडवगन, को शनिवार (6 दिसंबर) को श्रीगोंदा से गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद मामले में कई नए मुलासे सामने आ रहे हैं। शेटे पर आरोप है कि उसने कल्पना भगवत के साथ मिलकर फर्जी IAS अधिकारियों की एक नकली सूची तैयार की थी। जांच में यह भी

सामने आया है कि शेटे ने ही कल्पना की पहचान अन्य सहयोगियों से करवाकर ठगी के नेटवर्क को विस्तार देने में भूमिका निभाई। पुलिस के अनुसार, इसी फर्जी सूची के आधार पर लोगों को झांसा देकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शेटे को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 9 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं, मुख्य आरोपी कल्पना भगवत को न्यायिक हिरासत में भेजा

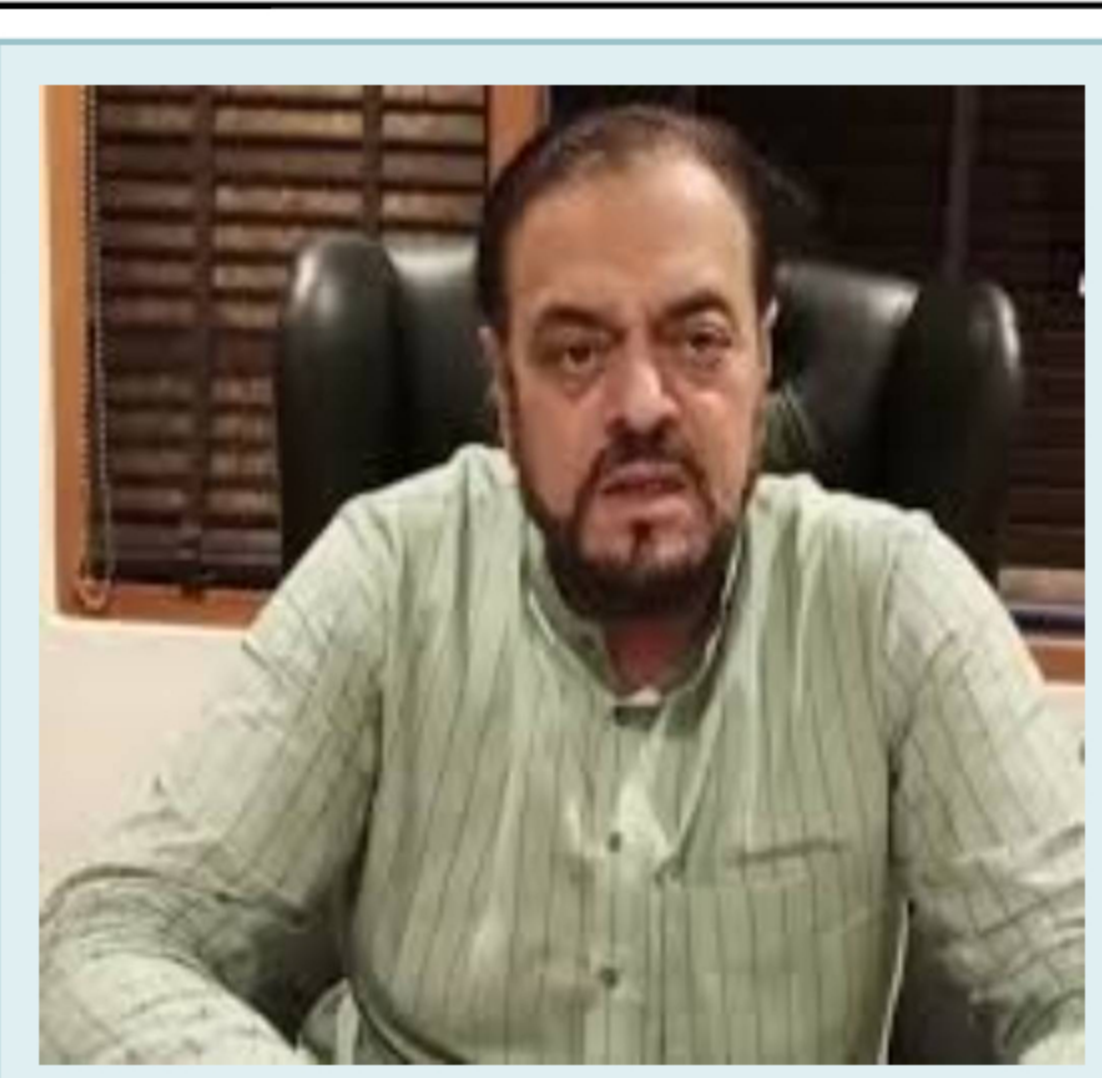
गया है। इस मामले में इससे पहले उसका अफगान मूल का मित्र, एक फर्जी "ओएसडी", और अन्य सहयोगी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शेटे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच और व्यापक दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि अब तक किसी भी प्रकार का राष्ट्रविरोधी या संदिग्ध विदेशी कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन सभी वितीय लेन-देन, दस्तावेज़ और आरोपियों के नेटवर्क की गहन जांच जारी है।



शिक्षक की शर्मनाक हरकत: कक्षा में शराबी 'गुरुजी' ने बच्चों से किया दुर्व्यवहार

माहर (नांदेड़) — शेकापुर स्थित जिला परिषद स्कूल में कार्यरत शिक्षक अनंत वर्मा का नशे में धुत होकर किया गया हंगामा सामने आया है। शराब के नशे में उन्होंने कक्षा में प्रवेश कर छात्रों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऊटपटांग हरकतों की और अपमानजनक व्यवहार किया। यह पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। घटना के बाद शेकापुर के अभिभावकों और ग्रामीण बेहद नाराज़ हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से अनंत वर्मा को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों की शैक्षणिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है।

अभिभावकों का आरोप है कि यह केवल एक शिक्षक की व्यक्तिगत गलती नहीं, बल्कि स्कूल प्रबंधन की निगरानी और जिम्मेदारी में गंभीर चूक है। इस घटना ने "गुरु" जैसी सम्मानित उपाधि की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और पूरे शिक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



मुंबई, 6 दिसम्बर 2025 — अब आजमी (Samajwadi Party) ने भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर दिए गए बयान में कहा कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे थे। क्योंकि उस वक्त कई मुस्लिम नेताओं — जिनमें मुहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे — ने अलग मुस्लिम-राष्ट्र की मांग की थी।

बंटवारे के वक्त मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे — लेकिन बाबा साहेब ने कहा: 'नहीं'

लेकिन, आजमी ने कहा कि आंबेडकर ने उस रूप में उस मांग का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नया भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई — सभी धर्मों और समुदायों के लिए होगा, जहाँ सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। आजमी ने आगे कहा कि आंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि मुसलमानों और अन्य वर्गों के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि अगर आज हम

किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं — तो यह संभव हुआ आंबेडकर द्वारा दी गई संवैधानिक शक्ति के कारण। सपा नेता ने कहा कि आंबेडकर का संघर्ष और उनकी विचारधारा हमें आज भी मार्गदर्शित करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश आंबेडकर की उस सोच को कभी नहीं भूल सकता — जिसमें जात-पात, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं

था, बल्कि समान अधिकार, न्याय और समाजिक समरसता थी। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे आंबेडकर की पुण्यतिथि हो या जन्मदिन — हर अवसर पर उन्हें सम्मान देना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए अधिकार-सशक्तिकरण की भावना ने भारत को एक समावेशी, धर्म-निरपेक्ष गणराज्य का रूप दिया है, और आज के समय में उनकी यही विचारधारा हमें जोड़ने वाली डोर हो सकती है।

परभणी-वसमत रोड पर भीषण टक्कर: तीन की मौत, दो गंभीर



परभणी-वसमत राज्य मार्ग पर राहदाही पाटी के पास शुक्रवार देर रात दो कारों की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत पर मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में बाबुराव दत्ताराव साखरे, कौताबाई कातारे और विमलबाई जाधव शामिल हैं। घटना के बाद वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से घायलों को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ताड़कलस पुलिस ने क्रेटा चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

नांदेड़ ऑनर किलिंग: आठवां आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को 8 लाख की मदद और सरकारी नौकरी का आश्वासन



नांदेड़ शहर में हुए सक्षम ताटे ऑनर किलिंग प्रकरण में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आंतरजातीय प्रेम संबंध से जुड़े इस सनसनीखेज मामले में अब पुलिस ने आठवां आरोपी आदित्य सोनमनकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उसे और हाल ही में गिरफ्तार हुए अमन शिरसे को 10 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित इतवारा, संघसेन नगर निवासी 20 वर्षीय सक्षम ताटे और सिद्धनाथपुरी की 19 वर्षीय आंचल मामीलवाड के बीच पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध थे। लेकिन सक्षम के दूसरी जाति से होने के कारण आंचल के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। इसी जातीय विरोध ने इस प्रेम कहानी को एक भयावह मोड़ दे दिया। 27 नवंबर को मिलिंद नगर इलाके में आंचल के परिवारजनों और उनके साथियों ने सक्षम को घेरकर पहले गोली चलाई और बाद में पत्थर मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद भावुक क्षणों में आंचल ने सक्षम के अंतिम संस्कार के दौरान उसके पार्थिव शरीर के साथ विवाह की रस्में निभाईं, जिससे यह मामला पूरे राज्य में चर्चित हो गया। इस केस में अब तक लड़की के माता-पिता, दो भाइयों और तीन सहयोगियों सहित कुल आठ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग भाई को बाल सुधारगृह में रखा गया है। इसी बीच राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की

सहायता के लिए कदम बढ़ाए हैं। समाज कल्याण विभाग ने ताटे परिवार को 8 लाख 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद मंजूर की है। इसमें से 4 लाख 12 हजार 500 रुपये की पहली किस्त परिवार के खाते में जमा कर दी गई है। शेष राशि चार्जशीट दाखिल होने पर दी जाएगी। साथ ही, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सक्षम ताटे की हत्या ने समाज में जातीय कट्टरता और ऑनर किलिंग जैसे अपराधों पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।



शादी में आठ दिन शेष, दूल्हा रेड-लाइट एरिया से रंगे हाथ पकड़ा गया

हदगांव (संवाददाता)

हदगांव (नांदेड़) — 16 दिसंबर को दूल्हे की शादी तय थी और घर में तैयारियां ज़ोरों पर थीं। रिश्तेदारों में निमंत्रण-पत्र बाँटने के लिए वह हदगांव आया था, लेकिन इसी दौरान पुलिस की छापेमारी में वह एक रेड-लाइट एरिया से रंगे हाथ पकड़ा गया। गुरुवार रात अर्धापूर पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कदम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में यह पूरा मामला उजागर हुआ। पुलिस को पहले से गुप्त सूचना मिली थी कि वाजपेयी नगर, नई आबादी और दत्तबर्डी क्षेत्र में अवैध देह व्यापार चल रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई न होने की शिकायत के बाद उच्च अधिकारियों ने यह मामला अर्धापूर पुलिस को सौंपा। इन इलाकों में पहले भी कई बार छापेमारी हो चुकी है, लेकिन कुछ समय बाद यह अवैध धंधा फिर शुरू हो जाता है। दूल्हे की गिरफ्तारी से दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया है। शादी के लिए तय किए गए शुभ

मुहूर्त, तैयार किए गए कपड़े, काई और व्यवस्थाओं पर अचानक संकट खड़ा हो गया है। परिजनों के लिए यह घटना सामाजिक बदनामी और मानसिक आघात का कारण बन गई है। पुलिस अधीक्षक अभिनाश कुमार ने कहा कि जिले में अवैध देह व्यापार के खिलाफ लगातार और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तथा इसमें शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय नागरिकों का भी कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्त निगरानी आवश्यक है, ताकि शहर का सामाजिक वातावरण सुरक्षित और सम्मानजनक बना रहे। फिलहाल दूल्हा न्यायिक हिरासत में है और उस पर लगे आरोपों ने उसके विवाह और भविष्य दोनों पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। यह घटना समाज के लिए एक बार फिर चेतावनी है कि बड़े पारिवारिक आयोजनों से पहले केवल तैयारी ही नहीं, बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी की कसौटी पर भी स्वयं को खरा साबित करना आवश्यक है।